



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2018/चैत्र 14, 1940

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2018/CHAITRA 14, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2018

मामला सं. ओ. आई. 6/2018

विषय - चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड से "सौर माड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

फा. सं. 06/9/2018-डीजीएडी.—मै. रीनिव सिस इंडिया प्रा. लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड से "सौर माड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जाँच के लिए विचाराधीन उत्पाद "सौर माड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट" है। यह सोलर पीवी (फोटो वोल्टेक) माड्यूल के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉलिमर आधारित घटक है। ईवीए शीट का प्रयोग एंथेशन और कुशनिंग

कार्य करके सोलर पीवी सेलों के एनकेप्सुलेशन के लिए किया जाता है। यह एक अनिवार्य संघटक है जो ग्लास, सेल और बैकशीट को जोड़े रखता है और उसके सेवा के जीवन काल के दौरान माड्यूल को यांत्रिक रूप से सहारा देता है।

3. ईवीए शीट एक्सट्रूजन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके निर्मित प्लास्टिक शीटिंग और फिल्मों की श्रेणी में आती है। यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री, ट्यूबुलर या आटोक्लेव प्रक्रिया का मुख्यतः प्रयोग करके पालीमराइज्ड पालीएथिलीन का एक कोपोलीमर है।

4. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे माड्यूल विनिर्माताओं द्वारा यथा अपेक्षित सभी चौड़ाइयों और सभी मोटाइयों की ईवीए शीटों का उत्पादन कर सकते हैं।

5. वर्तमान जाँच में पीयूसी के लिए माप की इकाई एमटी में भार है। विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर एचएस कोड 3901, 3920 और 3921 के अधीन आयातित किया जाता है। तथापि आयात अन्य एचएस कोडों के अधीन भी हो सकते हैं इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद का वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

7. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तु है। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

8. इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह याचिका मै. रीनिव सिस इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर की गई है जो भारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने मै. विशाखा रीनिवेबल्स प्रा. लि. और मै. एलायड ग्लासेस प्रा. लि. जो संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं, से समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। भारत में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक अर्थात् मै. ब्रिज फुट केयर है। मै. रीनिव सिस इंडिया प्रा. लिमिटेड ने संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात नहीं किया है और न तो वे संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।

10. इसलिए, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता जिसके पास वर्तमान में कुल घरेलू उत्पादन का एक 'प्रमुख हिस्सा' है, नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश

11. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड हैं।

सामान्य मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन लागत के आधार पर उसे विधिवत रूप से समायोजित करके, किया है।

13. तथापि, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, उत्पादकों/निर्यातकों को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट कर सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- क. कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

14. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड के लिए भी सामान्य मूल्य का परिकलन किया है क्योंकि वे उक्त देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में न तो प्रकाशित स्रोतों से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ रहे थे और न ही कोई विश्वसनीय सूचना जुटा पाये थे।

15. अतः प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य के साथ ही आगे की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

निर्यात कीमत

16. याचिकाकर्ता ने भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएस से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग करके निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा और पत्तन प्रहस्तन व्ययों, अंतर्देशीय भाड़े, ऋण लागत, कमीशन और वैट (केवल चीन के लिए) के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। तथापि, यदि निर्यातक के आकड़े प्रस्तुत किए और सत्यापित किए जाते हैं तो प्राधिकारी उन पर भरोसा करना चाहेंगे।

पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के सभी संबद्ध देशों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने अनुमान लगाया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

18. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन करने के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा, भारी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

19. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जाँच अवधि

20. जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 तक की है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016 – मार्च, 2017 और जाँच अवधि के आकड़ों पर विचार किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं से नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग से अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,****5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

26. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

27. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निदिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2018

Case No. O.I. 6/2018

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module” from China PR, Malaysia, Saudi Arabia, South Korea and Thailand.

F. No. 6/9/2018-DGAD.—M/s. RenewSys India Private Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to

as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module” (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from China PR, Malaysia, Saudi Arabia, South Korea and Thailand.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module”. It is the polymer based component used in the manufacturing of solar PV (Photo Voltaic) modules. EVA sheet is used for encapsulation of solar PV cells performing adhesion and cushioning functions. This is one of the most essential component which keeps glass, cell and backsheet integrated and support the module mechanically during its service life time.
3. The EVA sheet falls in the category of plastic sheeting and films made using extrusion technology. It is a thermoplastic material, a copolymer of Polyethylene, polymerized using tubular or autoclave process mainly.
4. The petitioner has claimed that they can produce all the widths and all the thicknesses of the EVA sheets as required by the module manufacturers.
5. The unit of measurement for the PUC in the present investigation is weight in MT. The product under consideration is generally imported under HS code 3901, 3920 and 3921. However, import can also take place under other HS codes, therefore, it is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

LIKE ARTICLE

6. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

7. The petitioner has submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. The subject goods produced by the petitioner company and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules.
8. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

9. The petition has been filed by M/s RenewSys India Private Limited, who is the largest producer of the subject goods in India. The petitioner has also submitted support letters from M/s Vishakha Renewables Pvt. Ltd and M/s Allied Glasses Pvt. Ltd who are the producers of the subject goods. There is one more producer of the subject goods in India, namely M/s Brij Foot Care. They have not imported the PUC from the subject countries and are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
10. The Authority, therefore, determines that the petitioner who presently holds a “major proportion” of the total domestic production, constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

COUNTRIES INVOLVED

11. The countries involved in the present investigation are China PR, Malaysia, Saudi Arabia, South Korea and Thailand.

NORMAL VALUE

12. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 of Annexure I of the Rules. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted.
13. However, while submitting the questionnaire response producers/exporters may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacturing, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:
 - a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
 - b. Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
 - c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate
14. Further, the petitioner has also constructed the normal values for Malaysia, Saudi Arabia, South Korea, and Thailand as they were neither able to get any documentary evidence from published sources nor reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the said countries.
15. The Authority has, therefore, for the purpose of the initiation, decides to proceed with the normal value as constructed by the petitioner.

EXPORT PRICE

16. Petitioner has determined export price using DGCIS data to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been claimed on account of Ocean Freight, Marine insurance and port handling expenses, inland freight, credit cost, commission and vat (in case of China only). However, the Authority would like to rely on data of exporter in case the same are furnished and verified.

DUMPING MARGIN

17. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows positive dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margin is estimated to be above de minimis for all the subject countries.

INJURY AND CAUSAL LINK

18. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

19. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to

determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

20. The period of investigation (POI) is from 1st October 2016 to 30th September 2017. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16, Apr'16-Mar'17 and the period of investigation will be considered.

SUBMISSION OF INFORMATION

21. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

TIME LIMIT

23. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

25. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.
26. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
27. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

31. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

NON-COOPERATION

32. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority